Expenditure on publicity by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

3699. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the amount spent on publicity by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P.J. KURIEN): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा खादी विपणन निगम की स्थापना

3700. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग कमीशन खादी विपणन निगम की स्थापना करने का विचार रखता है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी उपयोगिता क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) जी, हां। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए एक विपणन विकास निगम की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। योजना आयोग से परामर्श करके की गई टिप्पणी के आधार पर इसकी जांच की गई थी। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से अनुरोध किया गया कि वह उक्त प्रस्ताव की पुन: जांच करें और एक प्रस्ताव सरकार के पास विचार करने के लिए भेजें। इस निगम की उपयोगिता क्या होगी और इस पर संभावित खर्चा कितना होगा यह बात खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही मालूम हो सकती है।

खादी और ग्रामोद्योग भवन द्वारा खरीदे गये भूखंड

3701. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली ने इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-II ओखला में दिल्ली विकास प्राधिकरण से कोई भूखंड खरीदा है; यदि हां, तो उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या उक्त भूखंड का उपयोग किया जा रहा है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नोएडा में कोई अन्य भूखड खरीदा जा रहा है और उस पर कुछ धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त संगठन द्वारा उस भूखंड का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Representation for enactment of New Acts on Industry

3702. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Federation of the Association of Small Industries of India have urged Government to enact Prompt Payment Act and Limited Pertnership Act;

(b) if so, the reasons for delay;

(c) what are the other suggestions made by the Federation to improve functioning of SSI units; and

(d) what are the current outstanding dues by National Small Industries Corporation to various Small Scale units all over the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND

RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P.J. KURIEN): (a) The Policy Statement laid in both Houses of Parliament on 6.8.91 includes the proposal to enact legislation on Prompt Payment Act and on Limited Partnership Act.

(b) The Bill on Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings to replace the Ordinance promulgated on 23.9.92 has been listed for introduction in Winter Session of Parliament. The proposed Limited Partnership Act is under active consideration of the Administrative Ministry, namely, the Ministry of Law, Justice and Company Affairs.

(c) Various suggestions have been made by different industry associations, including the Federation of the Association of Small Industries of India, to improve the functioning of SSI units. The Suggestions pertain to issues regarding credit, sickness, incentives and simplification of rules and procedures etc. These issues have also been envisaged in the policy statement for small scale units and were discussed in detail at the 42nd Meeting of the Small Scale Industries Board held on 24.8.92.

(d) The information is being collected by NSIC.

Transfer of certain projects from Bihar

3703. SHRI KAMESHWAR PASWAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of institutes earlier proposed to be set up in Bihar which have been transferred outside the state by the Central Government;

(b) whether it is a fact that the railway wagon factory; and National Film and Television Institute proposed to be set up in H.E.C. Complex Ranchi and the sponge iron plant in Chhota Nagpur region respectively have either been transferred or are in the process of being transferred;

(c) if so, what are the reasons therefor; and

(d) whether it is also a fact that the transfer of these projects is having an adverse effect on the development of the Chhota Nagpur-Santhal Pargana areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) The information is being collected and shall be laid on the Table of the House.

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की लखनऊ इकाई का पुनरुद्धार

3704. **श्री राम रतन राम:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 मार्च, 1992 को केन्द्रीय सरकार को स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की लखनऊ इकाई (शाखा) के पुनरुद्धार के लिए कोई पत्र लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) को पहले ही प्रेषित कर दिया गया है। बी॰आई॰एफ॰आर॰ की पहली सुनवाई 11.8.1992 को हुई थी। बी॰आई॰एफ॰आर॰ के निदेशानुसार, एक परामर्शी नियुक्त कर दिया गया है जो कि बी॰आई॰एफ॰आर॰ के माध्यम से प्रचालन अभिकरण को प्रस्तुत किए जाने हेतु, कम्पनी के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार करेगा।